Re. Demand for Privilege notice regarding AIIMS

श्री मंगनी लाल मंडल (बिहार): उपसभापति महोदय, मैं श्री राजनीति प्रसाद जी ने जो विषय उठाया है, उससे अपने आपको संबद्ध करता हूं। इसके साथ ही मुझे इसमें एक बिन्दु पर यह भी कहना है कि लोक सभा ने यह विधेयक पारित किया है, राज्य सभा ने यह विधेयक पारित किया है और और राष्ट्रपति जी के assent के लिए इस विधेयक को जाना है। यह पार्लियामेंट के खिलाफ हड़ताल है। पार्लियामेंट की जो sovereignty है, पार्लियामेंट की जो प्रमुखता है या उसकी जो शक्ति है, उस शक्ति के खिलाफ संसदीय लोकतंत्र में यह एक बड़ा अनर्थ हो रहा है कि पार्लियामेंट आने वाले दिनों में कल को कोई कानून नहीं पास कर सकता है और पार्लियामेंट के खिलाफ हड़ताल हो, यह संसदीय लोकतंत्र का अपमान है। तो मेरा कहना है कि सरकार को इस तरह की हरकत पर नियंत्रण करना चाहिए।

दूसरे, जैसा श्री राजनीति प्रसाद जी ने कहा है कि...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आप केवल ऐसोसिएट कीजिए।

श्री मंगनी लाल मंडल: चूंकि संसद ने यह कानून पास किया है, इसलिए वे सांसदों का उपचार नहीं करेंगे। ये दोनों बिन्दु, जो डाक्टरों ने कहे हैं, काफी गंभीर हैं। पार्लियामेंट अपना काम करेगी या नहीं करेगी?

श्री उपसभापति: पार्लियामेंट अपना काम जरूर करेगी।

श्री मंगनी लाल मंडल: ये आरक्षण विरोधी या संवैधानिक व्यवस्था के विरोधी तत्व क्या बाहर से पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे? इस पर विचार किया जाना चाहिए। सरकार को इस विषय पर (एसर्ट) करना चाहिए और जिन लोगों ने हड़ताल की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए।

प्रो॰ राम देव भंडारी (बिहार): उपसभापति महोदय, ये सरकार के डाक्टर हैं, सरकार इनको सेलेरी देती है। सर, यह पार्लियामेंट का अपमान है, यह संसद का अपमान है और इसके खिलाफ प्रिवलेज होना चाहिए। यह प्रिवलेज का ईशू है।

श्री मोतिउर रहमान (बिहार): प्रिवलेज होना चाहिए।

SHRI JANARDHANA POOJARY (Karnataka): Sir, it is a privilege issue. ...*(Interruptions)*...

प्रो॰ राम देव भंडारी: सर, ये सभी आरक्षण विरोधी ताकतें हैं, ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: See, it can be considered only if there is a privilege notice. ...*(Interruptions)*...

प्रो॰ राम देव भंडारी: ये सभी आरक्षण विरोधी ताकतें हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: If there is a privilege notice, then only it can be considered. ...*(Interruptions)*...

KUMARI NIRMALA DESHPANDE (Nominated): Sir, I would like to associate myself and say that this is an insult to the Parliament of India. This should be taken seriously and the guilty should be punished by the Parliament of India.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I hope the Government will take note of this. ...*(Interruptions)*...

प्रो॰ राम देव भंडारी: सर, यह प्रिवलेज का ईशू है।

श्री उपसभापति: आप नोटिस दीजिए, उस पर कंसिडरेशन किया जाएगा।

प्रो॰ राम देव भंडारी: ठीक है, सर।

श्री उपसभापति: अगर प्रिवलेज का ईशू है तो नोटिस के बगैर कैसे कंसिडर करेंगे।

श्रीमती जया बच्चन (उत्तर प्रदेश): सर, मैं यह पूछना चाहती हूं कि ऐसा क्यों होता है कि अखबारों के थ्रू जो मैसेज हमको मलते हैं या अखबार में जो हम पढ़ते हैं, जैसा कि अभी सदस्य ने कहा AIIMS के बारे में, टेलीविजन में भी हमने देखा, इससे पहले मलेशिया के बारे में बातें हुईं मुझे यह समझ में नहीं आता कि जब ये विषय हम इस सदन में उठाते हैं तो गवर्नमेंट के सदस्य जो यहां बैठे हुए हैं, हमारे रिस्पॉसिबल मिनिस्टर हैं, why do they not give clarifications before these kinds of topics are brought into the House by other Members?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will tell you. I will clarify it. That is why there are certain procedures. If the hon. Members follow those procedures, the Government will respond. A lot of time I have pleaded with the hon. Members that whatever important issues they want to raise, they should raise it by way of Special Mentions, so that the Government is bound to reply to that rather than raising it in Zero Hour. First of all, let me clarify that there is nothing like Zero Hour in our Rules. The Zero Hour has no meaning. It is only for their satisfaction that the hon. Members raise it during Zero Hour. Now, what is not in the Rules, the Government is not bound to take note of. So, that is why. ...(*Interruptions*)...

श्री मंगनी लाल मंडल: महोदय, यह सदन भी महत्वपूर्ण है, इसमें कोई बात ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: प्लीज़ प्लीज़।

श्री मंगनी लाल मंडल: सरकार को संज्ञान लेना चाहिए।

श्री उपसभापति: मंडल जी, मुझे पूरी बात कह लेने दीजिए। आप बाद में जो भी कहना चाहे, कहें। इसलिए ज़ीरो ऑवर को रूल्स में निकाल दिया गया है after long consideration. There is no Zero Hour in our Rules. Again, somehow, a convention has built up for this and we are wasting a lot of time on it. I think all the hon. Members should sit and find out a procedure how these issues can be raised by way of Special Mentions during the same time. You make the Special Mention and it goes to the consideration of the Government. The Government will have to reply within a limited time and you get the reply.

अब जो ज़ीरो ऑवर है, इसमें रिप्लाई is not there; it will not be taken into account ...(**व्यवधान**)... इसके ऊपर बहस नहीं। आपने पूछा कि क्यों गवर्नमेंट रिस्पॉड नहीं करती, मैंने बता दिया है।

श्रीमती जया बच्चन: उपसभापति जी, मैं argue नहीं कर रही हूं, I just want my curiosity satisfied. How is it that such important issues do not get mention? It does not have to be in the House, but how is it that nobody from the Foreign Affairs Ministry has issued a statement, even through media, to the people of this country that whatever has happened in Malaysia is shameful. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I can't say all that. Mr. Minister would like to reply. ...(*Interruptions*)...

SHRI V. NARAYANASAMY (Puducherry): The Minister has issued a statement. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Mr. Narayanasamy is the new Minister, I did not know that! ...(*Interruptions*)... I feel sorry for the department! ...(*Interruptions*)...

SHRI V. NARAYANASAMY: The hon. Minister has made a statement in this regard and I am bringing it to the notice of the House and for your kind knowledge.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Narayanasamy, the Minister is on his legs.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Sir, I congratulate Mr. Narayanasamy for assuming the new post but then I feel very sorry for the department!

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): उपसभापति महोदय, आदरणीय सदस्या ने जो जिज्ञासा व्यक्त की है कि कुछ ऐसे मामले रहते हैं, जिनके संबंध में सरकार को स्वयं सदन को अवगत कराना चाहिए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अधिकांश ऐसे मामलों में सरकार सुओ मोटो स्टेटमेंट देती है, कुछ ऐसे मामले आते हैं, जो समाचारपत्रों में प्रकाशित होते हैं, उन पर सरकार अपने spokesman के जरिए मीडिया को अपना वक्तव्य प्रेषित करती है और कुछ ऐसे मामले आते हैं, जैसा आपने स्वयं कहा है कि हमेशा Rule and Procedure की प्रक्रिया के तहत जब कोई माननीय सदस्य Special Mention के माध्यम से, Calling Attention के माध्यम से या Short Duration Discussion के माध्यम से, phases के तहत ऐसे विषयों पर चर्चा चाहते हैं, तो उस चर्चा पर विधिवत सरकार सहमत होती है। ये चारों अलग-अलग phases में मामले रहते हैं, जिन पर सदन के जरिए हम लोग सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, वह अवगत कराते हैं। फिर भी मैं माननीय सदस्या की जिज्ञासा का आदर करता हूं और जो मामले इस सदन में आते हैं, हमारी हर संभव कोशिश यह रहती है कि उनके संबंध में हम सरकार की ओर से त्वरित कदम उठाएं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Maitreyan.

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, please spare me one minute.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let us not start a debate. ...(*Interruptions*)...

SHRI D. RAJA: Sir, there is no difference on these matters and the entire House has expressed concern. There should be no difficulty for the Government to take note of it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: But he has said that. ...(*Interruptions*)... The Government has responded to it. ...(*Interruptions*)...

श्री सुरेश पचौरी: उपसभापति जी, माननीय सदस्य ने यह बात उठाई है कि इस संबंध में सरकार का क्या मंतव्य है, तो मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि सरकार का इस संबंध में वक्तव्य आया है, फिर भी यदि सदन में और किसी दूसरे रूप में माननीय सदस्य इस पर चर्चा चाहते हैं, तो उस चर्चा में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं है, नियम और प्रक्रिया के तहत यदि वे चर्चा चाहते हैं, तो हम उस पर भी सहमत हैं।

DR. V. MAITREYAN (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman Sir, thank you very much for giving me an opportunity to say a few words.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have not admitted it. I have just allowed you. ...(*Interruptions*)... not on the subject. ...(*Interruptions*)...

DR. V. MAITREYAN: Sir, the brutal assassination of former Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi, is still fresh in our memory. He was killed in 1991 in Tamil Nadu during an election campaign by an LTTE suicide squad. It was due to the persistent efforts made by our Party leader and the former Chief Minister of Tamil Nadu, Madam Jayalalitha, that the LTTE was banned by the then Central Government led by late Shri P.V. Narasimha Rao. The ban is periodically reviewed and is in vogue even today. Whenever Madam takes over as the Chief Minister of Tamil Nadu, the activities of terrorist organisations like LTTE, TNLA, TNRP are all dealth with with an iron hand.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, you are going into details.

DR. V. MAITREYAN: But when we are not in power, the terrorist organisations have a field day. There are detailed reports of the seizure of arms and ammunition like AK-56, guns ...(*Interruptions*)...

MR DEPUTY CHAIRMAN: You may give that under a separate notice under rules. ...(*Interruptions*)... If you have any report, you must give it under rules. ...(*Interruptions*)...

SHRI A. RAJA: Sir, it is totally irrelevant. ...(*Interruptions*)...

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, all this is Unwarranted. He should talk only about the issue concerned. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You must give it under the ruies. ...(*Interruptions*)... If there is a terrorist activity, you may give notice under the rules so that it could be discussed. ...(*Interruptions*)...

DR. V. MAITREYAN: Last week, an unfortunate and condemnable incident took place in Erode. The Union Minister of State of Textiles, Mr. E.V.K.S. Elangovan, spoke in his constituency...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You leave it. ...(*Interruptions*)... Mr. Maitreyan. ...(*Interruptions*)... Special Mentions. ...(*Interruptions*)...

DR. V. MAITREYAN: The Central Government. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You give a separate notice for this ...(*Interruptions*)... Please...(*Interruptions*)... Shri Shantaram Laxman Naik ...(*Interruptions*)...

DR. V. MAITREYAN:*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing will go on record...(*Interruptions*)... That is not going on record ...(*Interruptions*)... That is not going on record...(*Interruptions*)... Special Mentions, please...(*Interruptions*)...

SPECIAL MENTIONS

Need to Cancel Re-Tendering of Stalls given to Displaced Persons by the Konkan Railway Corporation

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK (Goa): Sir, the House may be aware that the Government constituted Konkan Railway Corporation for the purpose of starting a railway route along the Konkan Coast going up to Goa and Mangalore. In this connection, vast tracks of land were acquired by the Government. There was also an agitation in Goa on grounds that ecology of the State would be affected on account of coastline alignment worked out by the Corporation.

There were also fears that Goa would be used as a corridor for the passing trains, and that, the needs of Goa would not be addressed, separately.

When the land was acquired, many had to surrender the agricultural activities that they were doing on the land. Some of the land losers were given jobs in the Corporation while some others were given stalls/telephone booths to be run by them at various stations.

Those who accepted the jobs are in the services of the Corporation, but those to whom the stalls were allotted, in their cases, the Corporation has re-tendered the stalls, which means despite the commitments given by the Corporation to the land losers the Corporation proposes to snatch away the stalls which the land losers, to whom they were allotted, are entitled to run upon payment of reasonable licence fee.

In these circumstances, if the Railway Ministry, which is funding the Corporation, does not intervene and takes steps to cancel the tenders issued with respect to the stalls allotted to the land losers, it would amount to a great hardship to these persons by a statutory Corporation. Thank you.

---

*Not recorded